

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १७

सम्पादक : मगनभाभी प्रभुवास देसाजी

अंक ९

मुद्रक और प्रकाशक
जीवनजी डाह्याभाभी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० २ मजी, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें ६
विदेशमें ८; शि० १४

बेचैन करनेवाली खबर

फाइनेंस बिल पर हुआ बहुसंका जवाब देते हुए लोकसभामें ता० १६ अप्रैलको अर्थमंत्री श्री सी० डी० देशमुखने नमक-कर जारी करनेके सुझावोंका जिक्त किया। जिस विषय पर अपना मत प्रगट करते हुए उन्होंने कहा :

“जिस सवालको अनिश्चित कालके लिये छोड़नेका विचार नहीं है। अपयुक्त अवसर आने पर उसका विचार करना पड़ेगा। लेकिन मैं यह नहीं मानता कि वह अवसर आ गया है। हां, मैं यह मानता हूँ कि वह आ सकता है।” (‘हिन्दुस्तान टाइम्स’, १७-४-५३)

अच्छा होता अगर अर्थमंत्रीने यह भी बताया होता कि वह अपयुक्त समय कब आनेवाला है, मौजूदा समयको वे अपयुक्त क्यों नहीं मानते, और उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह आ सकता है? क्या श्री देशमुख भारत-सरकारको अपने मतके पक्षमें लानेकी ही वाट देख रहे हैं? जो हो, हम सब लोगोंको यह बात याद रहनी चाहिये कि विदेशी सरकारके खिलाफ हमारे अहिंसक विद्रोहका ताना-बाना नमक, शराब और कपड़ा आदि वस्तुओंके आसपास ही बुना गया था। जिन विषयोंमें अपने निर्धारित युद्देश्यके लिये लड़ते लड़ते ही स्वतंत्रताके प्रति हमारे प्रेम और उसकी प्राप्तिके लिये लड़नेकी हमारी भावनाने अहिंसक विद्रोहका रूप पाया था। ऐसी कोभी विशेष बात तो नहीं थी जिसके कारण हमने उस समय जिस करका विरोध करना ठीक माना, लेकिन जो अब नहीं रह गयी है।

जैसा कि गांधीजीने कहा था, “नमक-करके अत्याचारका फल सबको अकसा भोगना पड़ता है। . . . उसकी सबसे कड़ी मार गरीबों पर पड़ती है। . . . छोटा बच्चा, अपाहिज और वृद्ध सब लोगोंको जिस अन्यायपूर्ण करसे समान कष्ट है। . . .”

“पानीको छोड़ दें, तो नमकके सिवा और दूसरी कोभी चीज नहीं जिस पर कर लगाकर सरकार अपनी लूटका विस्तार लाखों-करोड़ों भूखों, बीमारों, लूठों-लंगडों और अकदम निराधार अस-हायों तक कर सके। मनुष्यकी चतुराबी हर मनुष्य पर लगनेवाले और अधिकसे अधिक जिस अमानुषिक करकी कल्पना कर सकती है, यह कर वैसा ही है।”

जिसलिये हमें कहना पड़ता है कि अर्थमंत्रीके ये विचार बहुत बेचैन करनेवाले हैं और उनका समय रहते विरोध होना चाहिये।

२०-४-५३
(अंग्रेजीसे)

मगनभाभी देसाजी

हमारा अनोखा मिशन

[चांडिल सर्वोदय-सम्मेलनमें ता० ७-३-५३ को दिये गये विनोबाके पहले दिनके भाषणको पहली किस्त।]

१

पू० किशोरलालभाभी

जैसा कि शंकरराव देवने किया, मैं भी पू० किशोरलालभाभीके स्मरणसे जिसका आरम्भ करना चाहता हूँ। जो अक महान् कार्य अश्वरने हमें सौंपा है, और जिसकी हमने अश्वरके और जनताके सामने दीक्षा ली है, उस काममें वे अत्यन्त तन्मय थे। गीताने जीवनकी कुंजी हमें बतायी थी—यों कहकर कि कर्ममें अकर्म हो सकता है और अकर्ममें भी कर्म हो सकता है। वे शरीरसे बहुत कमजोर थे, जिसलिये जिसे हम स्थूल कर्म कहते हैं, वह वे बहुत नहीं कर पाते थे, तो भी चौबीस घंटे वे कुछ-न-कुछ करते ही रहते थे। फिर भी उस कर्मका स्थूल आकार बहुत बड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन उन्होंने हमें यह बताया कि कर्म न कर सकनेकी हालतमें भी कितना महान् कार्य हो सकता है। जिनके हृदय निर्मल होते हैं, परमेश्वरकी कृपासे जिनके राग-द्वेष धुल गये हैं, असे मनुष्योंकी केवल हस्ती ही बहुत काम कर जाती है। असे जो भी थोड़े लोग दुनियामें प्रकट होते हैं, उनमें मैं किशोरलालभाभीकी गिनती करता हूँ। बापूके पीछे उनका हम लोगोंको सहारा था और वे अपने सहज सौजन्यसे हम लोगोंको सम्हाल लेते थे। अतनी शक्ति हममें से दूसरे किसीमें अभी तक प्रकट नहीं हुयी है। जिसलिये उनका अभाव हम लोगोंको बहुत महसूस होता है और होता रहेगा। उस अभावकी पूर्ति हम अपने आपस-आपसके सद्भावसे और सीहादसे ही कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वैसा सीहाद, सौजन्य, सद्भाव और बंधुभाव हम लोगोंमें रहेगा, ताकि हमारे जरिये अश्वरका कार्य संपन्न हो।

नये सालके लिये संबल

हम अक कार्यकर्ता-जमात हैं। यहां सम्मेलनमें आते हैं, तो कुछ बोल भी लेते हैं। लेकिन यह बोलना भी हमारा काम ही होता है। वह कोभी केवल वक्तृत्व नहीं हो सकता; कर्तृत्वका ही हिस्सा होता है। असे जो हम लोग अकत्रित होते हैं, साल भर कुछ काम करके नारायणको वह समर्पण करनेके लिये आते हैं और दूसरे सालके लिये कुछ संबल लेकर जाना चाहते हैं। असे मौकों पर कुछ विचार-विनिमय, विचारोंकी लेन-देन कर लेते हैं। आज हमें असी दृष्टिसे हमारे कामके पीछे जो भूमिका है, वह देख लेनी चाहिये; कार्यका जो संशोधन करना है, उस पर भी नजर डालनी चाहिये। ‘कार्य-पद्धति’, ‘कार्यक्रम’ और ‘कार्य-रचना’ जिन तीनों पर हमें थोड़ा विचार कर लेना चाहिये।

अखिल जागतिक दृष्टि

हम दुनियाके किता भी गोशम क्यों न काम करते हों, आज दुनियाको हालत ऐसी नहीं है कि सारी दुनिया पर नजर डाले बगैर हमारा काम चल सके। दुनियामें जो ताकतें काम कर रही हैं, जो नय प्रवाह शुरू हुए हैं, कल्पनाओं और भावनाओंका जो संस्पर्श और संवष हो रहा है, उसको तरफ ध्यान देकर, उस पर सतत नजर रखकर ही जो भी छोटा-सा कदम हम उठाना चाहें, उठा सकते हैं। समुचित दृष्टिके बिना केवल कर्म अंधा हो जायगा। जिसलिये दुनियाको हालतका खयाल करना होता है। आज हम देख रहे हैं कि दुनियाकी हालत बहुत चंचल है। जितना ही नहीं बहुत कुछ स्फोटक भा है। यानी उसमें कभी खतरोंकी संभावना भरा है और कह नहीं सकते कि किस समय उसमें से ज्वालामुखीका स्फोट होगा। यह कुछ नाहक भयावना चित्र में नहीं खांच रहा हूं। जिससे भयभात होनेका मेरा खिरादा नहीं है, न आपको ही मैं भयभीत बनाना चाहता हूं। बल्कि जो हालत है, सिर्फ उस ओर ध्यान खांचना चाहता हूं। कहा नहीं जा सकता कि दुनियामें किस क्षण क्या होगा। ऐसी अस्थिर मनःस्थिति और पारःस्थिति आज दुनियामें है।

विपरीत परिस्थिति

एक-दो महीने पहलेकी बात है। दिल्लीमें कुछ ज्ञानी, विद्वान अेकत्रित हुए थे और उन्होंने अहिंसाके दर्शनके बारेमें कुछ चिन्तन-मनन, विमर्श किया। वह अखबारोंमें आता रहा और हम पढ़ते रहे। उसमें हमारे पूं राजेन्द्रबाबूने जिज्ञा किया था कि "आज कोश्री भा देश यह हिंमत नहीं कर रहा है कि हम सैन्यके बगैर चलायग।" उन्होंने जिस बातका भी दुःख प्रगट किया कि "बावजूद जिसके कि गांधीजोंको सिखावन हमने उनके श्रोमुखसे सीधा अपने कानोंसे सुना है और बावजूद जिसके कि हमने उनके साथ कुछ काम भी किया है, हिन्दुस्तान भी आज ऐसी हिंमत नहीं कर पा रहा है।" हमारे महान नेता पंडित नेहरू कथा मर्तबा बोल चुके हैं कि दुनियाका कोश्री मसला शस्त्र-बलसे हल नहीं हो सकता। हमारे ये भाओ, जो देशका नेतृत्व कर रहे हैं और जिन पर यह जिम्मेवारी देशने डाली है, अहिंसाको दिलसे मानते हैं। उनका हिंसा पर विश्वास नहीं है। फिर भी यह हालत है कि सेनाकी बनाने-बढ़ानेकी, उसको मजबूत करनेकी जिम्मेवारी उनको माननी पड़ती है। जिस तरह विचित्र परिस्थितिमें हम पड़े हैं।

दिल और विभागका संघर्ष

स्थिति यह है कि श्रद्धा अेक वस्तु पर है, असा हमको आभास होता है, और क्रिया दूसरी ही करनी पड़ती है। हम चाहते तो यह है कि सारे हिन्दुस्तानमें और दुनियामें अहिंसा चले, हम अेक-दूसरेसे न डरें, बल्कि अेक-दूसरेको प्यारसे जीतें। प्यार ही कामयाब हो सकता है और सबको वह जोत सकता है, असा विश्वास दिलमें भरा है। तिस पर भी अेक दूसरी चीज हममें है, जिसे बुद्धि नाम दिया जाता है। वैसे वह भी हृदयका अेक हिस्सा है, और हृदय भी उसका अेक हिस्सा है और यों दोनों मिले-जुले हैं, फिर भी हृदय कहता है कि हिंसासे कोश्री भी मसला हल नहीं होगा। अेक मसला हल होता-सा दिखेगा, तो उसमें से दूसरे दसों नये मसले पैदा होंगे। लेकिन बुद्धि तो तीनों गुणोंसे भरी है। उसमें कुछ विचारकी शक्ति है, कुछ आवरण भी है, कुछ दर्शन है और कुछ अदर्शन है। ऐसी हमारी संमिश्र बुद्धि हमें कहती है कि "हम सेनाको हटा नहीं सकते। जिस जनताके हम प्रतिनिधि हैं, वह जनता अतनी मजबूत नहीं है। उसमें वह योग्यता नहीं है। जिसलिये उसके प्रतिनिधिके नाते हम पर यह जिम्मेवारी आती है कि हम लश्कर बनायें, बढ़ायें और उसे

मजबूत करें।" ऐसी आज हालत है। दीखता यह है कि रचनात्मक कार्य करें। पर वह सिर्फ दिलकी अिच्छा है। बुद्धि कहती है कि "सेना बनानी होगी, जिसलिये सेना-यंत्र जिससे मजबूत बन सकेगा, उसे यंत्रोंको स्थान देना होगा।" जिनकी श्रद्धा चरखे पर कम है, उनकी बात में छोड़ देता हूं, लेकिन जिनकी श्रद्धा चरखे पर है, उनसे यह सवाल पूछा जाता है कि क्या चरखे और ग्रामोद्योगके जरिये आप युद्ध-यंत्र मजबूत बना सकते हैं या युद्ध-यंत्र खड़ा कर सकते हैं? तो उनकी बुद्धि, और हमारी बुद्धि भी, क्योंकि उनमें हम सम्मिलित हैं, कहती है कि नहीं, अिन छोटे-छोटे उद्योगोंके जरिये हम युद्ध-यंत्र सज्ज नहीं कर सकते हैं। कम्प्यूनिटी प्रोजेक्टके बारेमें सरकारकी अिच्छा यह रही है कि पांच लाख देहातोंमें वे चलें। अभी थोड़े देहातोंमें आरम्भ हुआ है। लेकिन अिच्छा है कि वह और व्यापक बने और उसके जरिये राष्ट्र समृद्ध हो, लक्ष्मीवान हो, गरीबी मिटे अित्यादि। पर अगर कल दुनियामें महायुद्ध छिड़ जाय, तो मैं कह नहीं सकता कि अेक भी कम्प्यूनिटी प्रोजेक्ट जारी रहेगा। और जिन्होंने अिस योजनाका अपक्रम किया, वे भी यह नहीं कह सकते कि वह जारी रहेगा। तब फौरन बुद्धि जोर करेगी और हृदय छिप जायेगा। हृदय पर बुद्धि गालिब हो जावेगी और कहेगी कि अब तो राष्ट्र-रक्षण ही मुख्य वस्तु है।

जादूकी कुर्सी

यह मैं आत्मनिरीक्षणके तौर पर बोल रहा हूं। जो आज वहां जिम्मेवारीके स्थान पर बैठे हुए हैं, उनकी जगह पर अगर हम बैठते, तो अभी वे जो कर रहे हैं उससे हम बहुत कुछ भिन्न करते, असा नहीं है। वह स्थान ही वसा है। वह जादूकी कुर्सी है। उस पर जो आरूढ़ होगा, उस पर अेक संकुचित, अेक सीमित, अेक बने-बनाये, अेक अस्वाधीन दायरेमें सोचनेकी जिम्मेवारी आती है। अैसे दायरेमें, जिसको मैंने 'अस्वाधीन' नाम दिया है, लाचारीसे दुनियाका ओष जिस दिशामें बहता हुआ दीख पड़ता है, उसी दिशामें सोचनेकी जिम्मेवारी उन पर आती है। बड़े-बड़े राष्ट्र — अमेरिका, रूस जैसे भी डरते हैं। वे अेक-दूसरेका डर रखते हैं। और कम ताकतवर राष्ट्र — पाकिस्तान और हिन्दुस्तान जैसे भी, असा ही डर रखते हैं। अिस तरह अेक-दूसरेका डर रखते हुए शस्त्र-बलसे, सैन्य-बलसे कोश्री मसला हल नहीं हो सकता, अैसे विश्वासके साथ हम शस्त्रबल और सैन्यबल पर आधार रखते हैं, उसका आधार नहीं छोड़ सकते।

दंभ नहीं, दयाजनक अवस्था

ऐसी विचित्र परिस्थितिमें हम हैं। और अगर कोश्री हमें दाम्भिक कहेगा, डोंगी कहेगा, तो वह असा कहनेका हकदार साबित होगा, यद्यपि उसका कथन सही नहीं होगा। यदि हमारे दिलमें कोश्री दूसरी बात है और उसे हम छिपाते हैं, तो हम जान-बूझकर डोंगी हैं। लेकिन जहां दिल उस बातको कबूल करता है और परिस्थितिजन्य बुद्धि दूसरी बात कहती है, अिस वास्ते लाचारीसे कोश्री बात करनी पड़ती है, तो वह दाम्भिकताकी नहीं, बल्कि दयाजनक स्थिति है। ऐसी दयाजनक स्थितिमें हम हैं।

अभी राजेन्द्रबाबूने बताया कि "सर्वोदय-समाज पर यह जिम्मेवारी है, क्योंकि लोगोंको उस समाजसे अपेक्षा है कि वहां समाज अपने मूल विचार पर कायम रहे और उसको आजकी हालतमें अमलमें लानेके लिये वातावरण तैयार करे। अगर सर्वोदय-समाज यह करेगा, तो आजकी सरकारको, जो कि हमारी राष्ट्रीय सरकार है, उसकी सर्वोत्तम मदद होगी। आज मान लीजिये कि हममें से कोश्री मंत्री बन जाय और कुछ मंत्र करने लगे, तो उसका वह मंत्र और उसका वह तंत्र, दोनों

मिल करके आजकी सरकारको अतनी मदद नहीं देगा, जितनी मदद बिना सैन्य-बलके जिस तरह समाज बन सकता है, उस दिशामें काम करनेसे वह देगा।

स्वतंत्र लोकशक्तिके निर्माणका कार्य

मुझे कभी-कभी लोग पूछते हैं कि आप बाहर क्यों रहते हैं? देशकी जिम्मेवारी आप क्यों नहीं उठाते? तो मैं कहता हूँ कि दो बैल जब गाड़ीमें लग चुके हैं वहां मैं एक तीसरा गाड़ीका बैल बनूंगा, तो उससे गाड़ीको क्या मदद मिलेगा? अगर मैं यह कर सकूँ कि रास्ता जरा ठीक बना दूँ, ताकि गाड़ी अचित दिशामें जाय, तो उस गाड़ीको मैं अधिक-से-अधिक मदद पहुंचा सकता हूँ। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर मैं बैल ही हूँ, तो मुझे बैल बनना ही चाहिये, वही काम करना चाहिये। मैं एक विशेष भाषामें बोल रहा हूँ। मैं अुम्मीद करता हूँ कि आप उस भाषाको सहन करेंगे। हमारी संस्कृतिमें बैलके लिये जितना आदर है, अतना मनुष्यके लिये भी नहीं है। और उसी अर्थमें मैं बोल रहा हूँ। जो राज्यकी धुरा उठाता है, उसे हम धुरंधर कहते हैं। धुरंधरके मानी होते हैं बैल! धुरंधर हमें बनना पड़ता है। लेकिन जो लोग धुरंधर बन चुके हैं, वे कहते हैं कि अब आप वही काम मत करिये जो हम कर रहे हैं। उस काममें आप मत लगिये, बल्कि जो कमियां हम महसूस करते हैं, उनकी पूर्ति अगर आप कर सकते हैं तो करें। ऐसी आशासे वे लोग हमारी तरफ देखते हैं। तो हमें यह ठीकसे समझना चाहिये और इस दृष्टिसे, जिसे मैं स्वतंत्र लोकशक्ति कहता हूँ, वह जिससे निर्माण हो, उसे ही काममें लग जाना चाहिये। तभी हम आजकी सरकारकी सच्ची मदद करेंगे और अपने देशकी समुचित सेवा कर सकेंगे।

दंडशक्तिके भिन्न लोकशक्ति

मैंने कहा कि 'हमें स्वतंत्र लोकशक्ति निर्माण करनी चाहिये।' मेरा अर्थ यह है कि हिंसाशक्तिकी विरोधी और दंडशक्तिके भिन्न ऐसी लोकशक्ति हमें प्रकट करनी चाहिये। आजकी हमारी जो सरकार है, उसके हाथमें हमने दंडशक्ति सौंप दी है। उस दंडशक्तिमें हिंसाका एक अंश जरूर है, फिर भी हम उसे 'हिंसा' नहीं कहना चाहते हैं। हिंसासे उसको अलग वर्गमें रखना चाहते हैं। हम उसे हिंसाशक्तिके भिन्न दंडशक्ति कहना चाहते हैं, क्योंकि वह शक्ति उनके हाथमें सारे समुदायने दी है। जिसलिये वह हिंसाशक्ति नहीं, निरी हिंसाशक्ति नहीं, पर दंडशक्ति है। उस दंडशक्तिका भी अपुयोग करनेका मौका न आये, ऐसी परिस्थिति देशमें निर्माण करना हमारा काम होगा। वह अगर हम करेंगे तो हमने स्वधर्म पहचाना और उस पर अमल करना जाना। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे और दंडशक्तिके अपुयोगसे ही जो जनसेवा हो सकती है उस जनसेवाका लोभ रखेंगे, तो जिस विशेष कार्यकी हमसे अपेक्षा की जा रही है उस कार्यकी, उस अपेक्षाको, हम पूर्ण नहीं कर सकेंगे। बल्कि संभव है कि हम बोझ-रूप भी साबित होंगे।

दयाका राज बनाना है, न कि दयाकी प्रजा

मैं कुछ थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूँ। मैंने कहा कि दंडशक्तिके आधार पर सेवाके कार्य हो सकते हैं और वैसे कार्य करनेके लिये ही हमने राज्य-शासन चाहा है और हाथमें लिया है। और जब तक समाजको वैसी जरूरत है, उस शासनकी जिम्मेवारी हम नहीं छोड़ना चाहते। सेवा तो उसमें से जरूर होगी, पर वह सेवा नहीं होगी, जिससे कि दंडशक्तिका अपुयोग ही न करना पड़े, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो। मैं मिसाल दूँ। लड़ाई चल रही है। सिपाही जख्मी हो रहे हैं। उन सिपाहियोंकी सेवामें जो लोग लगे हैं, वे भूतदयासे परिपूर्ण होते हैं। वे शत्रु-भिन्न तक नहीं देखते हैं और अपनी जान खतरेमें डालकर युद्ध-

क्षेत्रमें पहुंचते हैं। और ऐसी सेवा करते हैं, जो केवल माता ही अपने बच्चोंकी कर सकती है। जिसलिये वे दयालु होते हैं, जिसमें कोअी शक नहीं। वह सेवा कीमती है, यह हर कोअी जानता है। लेकिन युद्धको रोकनेका काम वे नहीं कर सकते। उनकी दया युद्धको मान्य करनेवाले समाजका एक हिस्सा है। जैसे एक यंत्रमें अनेक छोटे-बड़े चक्र होते हैं, वे एक-दूसरेसे भिन्न दिशाओंमें भी काम करते होंगे, फिर भी वे उस यंत्रके अंग ही हैं। तो एक ही युद्ध-यंत्रका एक अंग है सिपाहियोंको कत्ल किया जाय और उसी युद्ध-यंत्रका दूसरा अंग है जख्मी सिपाहियोंकी सेवा की जाय। उनको परस्पर विरोधी गतियां स्पष्ट हैं। एक क्रूर कार्य है, एक दया-कार्य है, यह हर कोअी जानता है। पर उस दयालु हृदयकी वह दया और उस क्रूर हृदयकी वह क्रूरता, दोनों मिल करके युद्ध बनता है। ये दोनों युद्ध बनाये रखनेवाले दो हिस्से हैं। कठोर वैज्ञानिक भाषामें बोलना है, तो युद्धको जब तक हमने कबूल किया है, तब तक चाहे हमने उसमें जख्मी सिपाहीकी सेवाका पेशा लिया हो, चाहे सिपाहीका पेशा लिया हो, हम दोनों युद्धके गुनहवार हैं। यह मैंने जिसलिये मिसाल दी कि सिर्फ हम दयालु कार्य करते हैं, जिसलिये यह नहीं समझना चाहिये कि हम दयाका राज्य बना सकेंगे। राज्य तो निष्ठुरताका है। उसके अन्दर दया जैसे रोटीके अन्दर नमक वैसे रुचि पैदा करनेका काम करती है। जख्मी सिपाहियोंकी उस सेवासे हिंसामें लज्जत पैदा होती है, युद्धमें रुचि पैदा होती है, परन्तु युद्धकी समाप्ति उस दयासे नहीं हो सकती। हम लोग इस तरहकी दयाका काम करें कि निष्ठुरताके राज्यमें दया प्रजाके नाते रहे, निर्दयताकी हुकूमतमें दया चले, तो हमने अपना असली काम नहीं किया। इस तरह जो काम दयाके दीख पड़ते हैं, जो काम रचनात्मक भी दीख पड़ते हैं, अन्हें हम दया और रचनाके लोभसे व्यापक दृष्टिके बिना ही उठा लें, तो कुछ तो सेवा हमसे बनेगी, पर वह सेवा नहीं बनेगी, जिसकी जिम्मेवारी हम पर है और जिसे हमने अपना तथा दुनियाने स्वधर्म माना है।

मनुष्यके हृदयका कानून

मैं दूसरी स्पष्ट मिसाल देता हूँ। मुझे हर कोअी पूछता है कि 'आपका वजन सरकार पर भी कुछ दीखता है, तो आप यह क्यों नहीं जोर लगाते कि सरकार कोअी कानून बना दे और बिना मुआवजेके भूमि-वितरणका कोअी मार्ग खोल दे? आप अपना वजन क्यों नहीं इस दिशामें अिस्तेमाल करते?' ऐसा बहुत मर्तबा लोग मुझसे पूछते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि 'भाओ, कानूनके मार्गको मैं रोकता नहीं हूँ। जिससे ज्यादा अगर और एक कदम आप मुझसे चाहते हैं—आपकी दिशामें, आपकी अिच्छित दिशामें—तो मैं कहता हूँ कि जो मार्ग मैंने अपनाया है, उसमें यदि मुझे पूरा यश, सोलह आने यश नहीं मिला; बारह आने, आठ आने भी मिला, तो कानूनके लिये सहूलियत होगी। एक तो मैं कानूनको बाधा नहीं पहुंचा रहा हूँ। और दूसरे, मैं कानूनको सहूलियत दे रहा हूँ। उसके लिये अनुकूल वातावरण बना रहा हूँ, ताकि कानून आसानीसे बनाया जा सके। पर जिससे भी एक कदम आगे मैं आपकी दिशामें जाऊँ और यही रटन रटूँ कि 'कानूनके बिना यह काम नहीं होगा, कानून बनाना चाहिये', तो मैं स्वधर्मविहीन साबित हूँगा। मेरा वह धर्म नहीं है। मेरा धर्म तो यह माननेका है कि बिना कानूनकी मददसे जनताके हृदयमें हम ऐसे भाव निर्माण करें, ताकि कानून कुछ भी हो, लोग भूमिका बंटवारा करें। क्या किसी कानूनके कारण मातायें बच्चोंको दूध पिला रही हैं? तो मनुष्यके हृदयमें कोअी ऐसी शक्ति होती है, जिससे उसका जीवन समृद्ध होता है। मनुष्य प्रेम पर

भरोसा रखता है, प्रेमसे पैदा हुआ है, प्रेमसे पलता है और आखिर जब दुनियाको छोड़कर जाता है, तब भी प्रेमकी ही निगाहसे जरा विदगिर्द देख लेता है और उसके प्रेमी-जन अगर उसके दर्शनमें आते हैं, तो सुखसे देहको, दुनियाको छोड़कर वह जाता है। तो प्रेमकी शक्तिका जिस तरह अनुभव होते हुए भी उसको अधिक सामाजिक स्वरूपमें विकसित करनेकी हिम्मत रखनेके बजाय मैं अगर कानून-कानून रटता रहूँ, तो जनशक्ति निर्माण करके सरकार हमसे जो मदद अपेक्षित करती है, वह मदद मैंने दी, असा नहीं होगा। जिसलिसे दंडशक्तिसे भिन्न मैं जनशक्ति निर्माण करना चाहता हूँ। और हमें वह निर्माण करनी चाहिये। यह जो जनशक्ति हम निर्माण करना चाहते हैं, वह दंडशक्तिकी विरोधी है, असा मैं नहीं कहता। वह हिंसाकी विरोधी है। लेकिन मैं अतना ही कहता हूँ कि वह दंडशक्तिसे भिन्न है।

(अपूर्ण)

हरिजनसेवक

२ मजी

१९५३

भूदान-यज्ञ और शोषण-निवारण

वाचकोंसे प्रार्थना है कि वे मेरा ता० ४-४-५३ के 'हरिजन' में छपा 'भूदान-आन्दोलन' नामक लेख फिरसे देखें। उसमें मैंने श्री नारगोलकरके सवालका जिक्र किया था। वह लेख पढ़कर वे मुझे लिखते हैं कि उससे उनका समाधान नहीं हुआ। और अपने सवालके उस हिस्सेकी ओर वे मेरा ध्यान खींचते हैं, जहां पर उन्होंने कहा था कि, "बेजमीन किसानको भूदानसे कोअी सफलता या आनन्द प्राप्त हुआ, असा नहीं लगता है। जो चीज अन्यायसे उससे छीन ली गयी थी, उसको वापस लेनेके लिये उसे कोशिश करनेकी जरूरत नहीं पड़ती है। . . . बिना प्रयत्नसे मिली हुयी चीजकी गृहीताकी नजरमें कोअी कीमत नहीं होती। अतना ही नहीं, जिससे वह अपनी प्रगतिकी और व्यक्तित्वके विकासकी शक्ति खो बैठता है।"

और वे आगे बताते हैं कि, "जमीन छुड़वानेकी आज जो कोशिश हो रही है, उसमें भूमिहीनको कुछ भी स्थान नहीं—जिस मेरे आक्षेपका कोअी जवाब ही नहीं देता, असा मुझे बार-बार लगता है।"

और मिसालके तौर पर वे बताते हैं कि, "स्वातंत्र्य-युद्धमें आम जनताने कितना सहयोग दिया था। जिसका कारण यह था कि सहयोगके लिये उनको उस आन्दोलनमें काफी अवसर मिलता था।" वे लिखते हैं: "मैं १९४२ में बम्बयीमें था। जब पुलिस भीड़के ऊपर घुआं-बारूदका उपयोग करती थी, तो मकानोंमें ऊपरकी मंजिलोंमें रहनेवाली स्त्रियां पानीकी बालटियां भर भरकर नीचे फेंकती थीं। कितना छोटा काम! लेकिन जिससे उन सबको सत्याग्रह आन्दोलनमें भाग लेनेका आनन्द और समाधान मिलता था।" और आगे कहते हैं, "असा कुछ भी अवकाश जिस आन्दोलनमें भूमिहीनके लिये नहीं रखा गया है।"

श्री नारगोलकरकी शंका और ज्यादा साफ हो सके, जिसलिसे मैंने कुछ लम्बायीसे उनके पत्रका जिक्र किया। उनको जिस शंकाको मैं ठीक समझा था और उसका उत्तर भी मैंने अपने ऊपर बताये हुये लेखमें देनेकी चेष्टा की थी, असा मैं मानता हूँ। उसमें मैंने कहा था कि अगर भूदान-आन्दोलनमें दान देनेके सिवा और कुछ न हो, तो बेजमीन किसान मूक गृहीताका ही काम करेगा; कुदरती तौर पर उसकी और कोअी हैसियत हो ही नहीं

सकती। लेकिन मैंने अपने जवाबमें यह बतानेकी चेष्टा की थी कि जिस यज्ञकी पूर्णता भूमि लेने और देनेकी दोनों क्रियायें मिलकर होती हैं। देनेवाला समझे कि मैं दान देकर कोअी अपकार या मेहर-बानी नहीं लेकिन प्रायश्चित्त करता हूँ। और पानेवालेको चाहिये कि वह जमीन पाकर उसका पूरा फायदा अठानेके लिये अपनेको तैयार करे। यानी उसको भी अपनी आत्म-शुद्धि करनी है। श्री नारगोलकरकी यह बात हम मान लें कि लोगोंसे भूमि अन्यायसे छीन ली गयी थी। लेकिन यहां सवाल यह है कि अब जमीन ठीक न्यायसे कैसे बांटी जाय? जो बेजमीन हैं, उनको जमीन कैसे मिले? यह परिवर्तन सत्य और अहिंसासे कैसे हो सकेगा? यह सोचते हुये हम देखते हैं कि यदि भूमिहीन अपने शोषण-कार्यमें अपनी तरफसे सहकार नहीं देंगे, तो उनका शोषण जारी नहीं रहेगा। जमीनवाले भी जमीनसे पैदाबिषा चाहते हैं; जिसलिसे उनको किसानों और मजदूरोंका सहकार मिलना चाहिये। यह सहकार मिलता है, इसलिसे वे लोग अपनी जमीनकी मालिकीके दावेसे बेजमीन श्रमजीवियोंका शोषण करते रहते हैं। यदि बेजमीन श्रमजीवी वर्ग यह समझ जाय कि हमारे सहकारके बिना जमीनवाले शोषण नहीं कर सकते और जिस तरह वे अपने शोषणको रोक सकते हैं, तो हमको सवालका अहिंसक हल मिल गया। जैसे कि गांधीजीने अपने 'आर्थिक समानता' नामक लेखमें ('हरिजनसेवक', ११-४-५३) बताया है: "कोअी धनवान (यहां पर हम जमीन-मालिक भी मान लें) गरीबोंके सहकारके बिना धन नहीं कमा सकता। मनुष्यको अपनी हिंसक शक्तिका भान है। . . . मगर अहिंसक शक्तिका भान भी धीरे-धीरे किन्तु अचूक रीतिसे बढ़ने लगा। यह भान गरीबोंमें प्रसार पा जाये, तो वे बलवान बनें और आर्थिक असमानताको, जिसके कि वे शिकार बने हुये हैं, अहिंसक तरीकेसे दूर करना सीख लें।"

जिस परसे मालूम होगा कि भूमिदान-यज्ञ सचमुच हिन्दुस्तानका जमीनका सवाल हल करनेका अकेला अहिंसक मार्ग है और जिसमें भूमिहीनोंके लिये भी अपने संगठनका कार्यक्रम भरा पड़ा है। रचनात्मक कार्यक्रमके जरिये हमें अिन लोगोंका ठोस संगठन करना चाहिये। उसमें जो अहिंसक क्रांतिकी संभावना और शक्ति है, उसका उन्हें दर्शन कराना चाहिये। उसी खयालसे मैंने कहा था कि भूदानका उनको (बेजमीनोंके) लिये भी अकेल सन्देश है। और वह यह है कि वे भी जग जायं और समझ लें कि हमें खेती और घरेलू अद्योग-धन्धोंके समन्वयवाली विकेन्द्रित और स्वावलम्बी अर्थ-रचनामें बुद्धिपूर्वक सहयोग देना है, जिसकी स्थापना भूदान-आन्दोलन भारतमें करना चाहता है।

परन्तु शायद यह उत्तर श्री नारगोलकरको पसन्द नहीं आया था फिर समझमें नहीं आया। शायद उनका खयाल असा हो कि बेजमीनोंके लिये कुछ और काम सोचना चाहिये, जिसके जोरसे उन्हें भूमि मिलने लगे—यानी जमीन-मालिकोंको अपनी भूमि देनी पड़े। यदि मेरी यह धारणा सही हो, तो उनका यह खयाल ठीक नहीं है। श्री विनोबाने बार-बार यह घोषित किया है कि वे अपना काम कानूनके या और किसी हिंसक बल पर नहीं करना चाहते। इसीमें उसकी खूबी है। और यही देखकर सब पक्षके लोगोंने जिस कार्यक्रमको पसन्द किया है।

श्री नारगोलकरका पत्र मिलनेके बाद उनसे मिलनेका भी मौका मुझे मिला। उन्होंने बताया और जिस बातसे वे हैरान थे कि बम्बयी-राज्यमें जमीन-मालिक खुद जोतनेके बहाने काश्तकारोंसे जमीनें छीन रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि अकेल तरफसे जमीन-मालिक अपनी थोड़ी जमीन भूदान-यज्ञमें देकर प्रतिष्ठा पा रहे हैं और दूसरी तरफ अपने काश्तकारोंसे कानून छूटा हिस्सा लेनेके बजाय ज्यादा वसूल कर रहे हैं, जैसी कि

अनकी पुरानी नीति थी। असी फरियाद सूरत और खेड़ा जिलेसे भी सुननेमें आजी है। संभव है कि वह सही हो। बम्बई-राज्यका कानून काश्तकारको चंद हक देता है। उसको जमींदार निकाल नहीं सकता, सिवा कि वह खुद जमीन जोतना चाहे। और उसके लिये भी अंक मियाद बनी है, जिससे ज्यादा जमीन वह नहीं ले सकता। यदि जमींदार अपनी जमीन बेचना चाहे, तो पहला खरीदनेका हक काश्तकारको रहेगा। और भी इस तरहके हक बम्बई-राज्यमें कानूनसे किसानोंको दिये गये हैं। मैंने ऊपर जो गिनाये, सो मिसालकी तीर पर हैं। किसान इस कानूनका फायदा जरूर अुठा सकते हैं। लगानके रूपमें वे छोटे हिस्सेसे ज्यादा न दें। जिसका फायदा यदि किसान अुठाना चाहें, तो वे संगठित रूपसे बलवान बनकर अुठा सकते हैं। परंतु जैसे अस्पृश्यता-निवारणका कानून बनने पर भी दूर-दूर देहातोंमें वह सिद्ध नहीं हुआ, वैसा इस कानूनका भी हो सकता है। धनी लोग जहां तक अनका बस चलेगा गरीबी और बेकारीका फायदा लेना नहीं छोड़ेंगे। परन्तु इसके मानी यह नहीं कि कानूनका अमल न हो। जरूर होना चाहिये। इसके लिये अंक ही रास्ता है। यदि सरकार और कार्यकर्ता लोग दोनों मिलकर धैर्यसे किसानोंमें काम करते रहें, तो यह उनके संगठित शांत बलसे बननेवाली चीज है। यह अंक बड़ा भारी कार्य बेजमीनोंको करना है, जिसका जिक्र मैंने संक्षेपमें अपने पिछले लेखमें किया था।

कार्यकर्ता लोग यदि इस दृष्टिसे अपना काम आगे बढ़ावें, तो अुन्हें पता चलेगा कि कैसे भूदान-यज्ञमें क्रांतिके बीज पड़े हैं। यह क्रांति अहिंसक होगी, सत्य-परायण होगी, यह हमें भूलना नहीं चाहिये।

२६-४-'५३

मगनभावी देसाजी

गांधीवाद

अगर गांधीवाद संकुचित पंथवादका ही दूसरा नाम है, तो वह मिटा देनेके काबिल है। मरनेके बाद अगर मुझे मालूम हो कि मैंने जिन चीजोंकी हिमायत की थी वे बिगड़कर पंथवाद बन गयी हैं, तो मेरी आत्माको गहरी चोट पहुंचेगी। हमें तो चुपचाप काम करते जाना है। कोअी यह न कहे कि मैं गांधीका अनुयायी हूं। मैं अपना ही अनुयायी बन जाऊं तो बहुत है। मैं जानता हूं कि मैं अपना कितना अपूर्ण अनुयायी हूं। क्योंकि मैं जिन विश्वासोंकी हिमायत करता हूं, उन पर पूर्ण अमल नहीं कर पाता हूं। आप लोग अनुयायी नहीं हैं, बल्कि स्वाध्यायमें, धर्मयात्रामें, सत्यकी शोधमें और सेवाकार्यमें मेरे साथी हैं।

हमें सत्य और अहिंसाको केवल व्यक्तियोंके ही अमलकी चीज नहीं बनाना है, बल्कि असी चीज बनाना है जिस पर समूह, जातियां और राष्ट्र भी अमल कर सकें। कम-से-कम मैं तो यही सपना देखता हूं। मैं तो इसीको सच्चा करनेके लिये जीता हूं और इसीकी कोशिश करते हुअे मरूंगा। मेरी श्रद्धा मुझे नित-नये सत्य खोज निकालनेमें मदद देती है। अहिंसा आत्माका गुण है और इस कारण हर व्यक्तिको जीवनकी सब बातोंमें अुस पर अमल करना चाहिये। अगर अुसका आचरण हर क्षेत्रमें नहीं हो सकता, तो अुसका व्यावहारिक मूल्य कुछ नहीं।

अिसमें झूठे बड़प्पन या सज्जनताके अभिमानका डर हमेशा रह सकेगा। अिसलिये आप अपनेको गांधी-सेवा-संघका सदस्य कहनेकी बजाय यही क्यों न करें कि सत्य और अहिंसाको हरअंक घरमें पहुंचायें और आप जहां भी हों, वहां सत्य और अहिंसाके ही वैयक्तिक प्रतिनिधि बनकर रहें।

('हरिजन', २-३-'४०)

श्री० क० गांधी

दक्षिण अफ्रीकामें सत्याग्रह

[दक्षिण अफ्रीकामें रंगीन लोग वहांके गिरे राज्यके संगठित बलके सामने जो शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रतिकार कर रहे हैं, वह केनियाके माजू-माजू आन्दोलनसे बिलकुल भिन्न है और यह अत्यन्त स्वागत योग्य है। अिस माजू-माजू आन्दोलनके बारेमें पाठकोंने ब्रिटिश पार्लियामेन्टके सदस्य श्री फेनर ब्रॉकवे जैसे शांति-प्रेमी सज्जनकी कलमसे लिखा लेख 'हरिजन' के पिछले अंकमें अवश्य पढ़ा होगा। दक्षिण अफ्रीकाका आन्दोलन हमारे विशेष आकर्षण, मदद और सहानुभूतिका अधिकारी है, क्योंकि वह गांधीजीके दक्षिण अफ्रीकाके अुस आन्दोलनसे अतिहासिक सम्बन्ध रखता है और अुसीकी आध्यात्मिक विरासत अिसे मिली है, अिसने दुनियाको सत्याग्रहका अनोखा हथियार दिया। वर्तमान आन्दोलन अब दो साल पुराना हो गया है और यह अीश्वरकी कृपा है कि जातीय नफरत और वैरकी बुनियादी भावनासे पैदा हुअी बहुत बड़ी कठिनायियों और रकावटोंके बावजूद अुसकी गति और विस्तार बढ़ रहा है। अिस दो साल पुरानी कहानीका सार अिग्लैंडके 'वार रेजिस्टर' नामक पत्रके वसंतकालीन अंक (१९५३) से नीचे दिया जाता है। आशा है अिससे पाठकोंको अपना ध्यान अिस आन्दोलन पर केन्द्रित करनेमें मदद मिलेगी। अिसमें केनियाके आन्दोलनकारियोंके लिये भी अंक सबक है, अिस पर अुन्हें खुद अपने और मानव-जातिके कल्याणके खातिर ध्यान देना चाहिये। क्योंकि आतंक और दुर्भाग्यसे अुसके द्वारा भड़काया जाने-वाला प्रति-आतंक — दोनोंको आधुनिक सम्य जगतसे देशनिकाला दे दिया जाना चाहिये और जंगली करार देना चाहिये, भले वह राज्यकी ओरसे फैलाया जाय या प्रजाकी ओरसे।

१८-४-'५३

—म० प्र०]

खुशीकी बात है कि लड़ाईका विरोध करनेवाले लोगोंकी आन्तरराष्ट्रीय संस्था (वार रेजिस्टर्स अिन्टरनेशनल) के सामने दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहके महत्त्व और मूल्यकी चर्चा करनेके लिये मुझसे कहा गया है। मैं अिस बातको सबसे बड़ा महत्त्व देता हूं कि हम २६ जून, १९५२ को शुरू हुअे अिस आन्दोलनको समझें और अुसका मजबूतसे मजबूत समर्थन करें।

दिसम्बर १९५१ में हुअे अपने ३९वें वार्षिक सम्मेलनमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेसने दक्षिण अफ्रीकाकी भारतीय कांग्रेसके सहयोगसे अन्यायपूर्ण कानूनोंके खिलाफ सामूहिक आन्दोलन शुरू करनेका निर्णय किया। कांग्रेसके अध्यक्ष डॉ० मोरोकाने डॉ० मलानको लिखा कि अगर कुछ अैसे कानून, जो "लोकतंत्रकी भावनाके खिलाफ, अन्यायपूर्ण, पक्षपात करनेवाले और मनुष्यके स्वाभाविक अधिकारोंके खिलाफ हैं," २९ फरवरी, १९५२ के पहले रद्द न कर दिये गये, तो अुन्हें अिन कानूनोंके विरोधमें आन्दोलन शुरू करना होगा। डॉ० मलानका लम्बा और सोच-विचार कर दिया हुआ जवाब २९ जनवरीको प्रकाशित हुआ था। अुन्होंने कहा कि "युरोपियनों और अफ्रीकनोंमें भेद करनेवाले लम्बे समयसे चले आ रहे कानूनोंको" रद्द करनेका सरकारका कोअी विरादा नहीं है। डॉ० मोरोकाके तीन मुद्दोंका जवाब देते हुअे डॉ० मलानने कहा:

१. "मेरे विचारसे आप यह महसूस करेंगे कि (बन्ट और युरोपियनोंके बीचके) ये भेद सनातन हैं, मनुष्यके पैदा किये हुअे नहीं हैं।"

२. "आपकी यह मांग है कि यूनियन अैसा राज्य न रहे, अिस पर युरोपियनोंका शासन हो।... अिस तरह जातीय मेल और समन्वय नहीं पैदा किया जा सकता। अैसी मांगोंको स्वीकार करना अनिवार्य रूपसे आबादीके सारे वर्गोंके लिये सर्वनाशको न्योतना है।"

३. "आपका तीसरा मुद्दा यह है कि जातीय भेद करनेवाले कानून प्रजाका दमन और अपमान करनेवाले हैं। आपकी यह बात भी बिलकुल गलत है।"

डॉ० मोरोकाने १८ फरवरी, १९५२ को जिसके जवाबमें लिखा कि :

"प्रस्तुत प्रश्न नसलके भेदका नहीं, बल्कि नागरिकताके अधिकारोंका है, जो मनुष्य द्वारा बनाये गये और कृत्रिम तौर पर लादे गये कानूनों द्वारा प्रजाके अंक भागको तो पूरे-पूरे दिये गये हैं, जबकि दूसरे भागको बिलकुल नहीं दिये गये हैं। अिन कानूनोंको लादनेका अद्देश्य स्वतंत्र समाजके नाते यूरोपियनोंकी अकरूपता कायम रखना नहीं, बल्कि अफ्रीकी लोगोंका व्यवस्थित शोषण जारी रखना है। . . .

"अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो सामूहिक आन्दोलन शुरू करनेका अिरादा रखती है, उसके सम्बन्धमें हम यह बताना चाहेंगे कि अरक्षित और मतदानके अधिकारसे वंचित लोगोंके नाते हमने जिस अन्यायको दूर करनेके दूसरे रास्ते खोजे, लेकिन अुसमें हमें सफलता नहीं मिली।

"अैसी हालतमें अफ्रीकी लोगोंके सामने सामूहिक आन्दोलन शुरू करनेके सिवा दूसरा कोअी रास्ता ही नहीं रह गया है। हम दृढ़तापूर्वक यह कहना चाहते हैं कि हमारी मंशा शांतिपूर्ण ढंगसे यह आन्दोलन चलानेकी है, और अगर जिसमें कोअी गड़बड़ी पैदा हुआ तो वह हमारी पैदा को हुआ नहीं होगा। सीधे प्रतिनिधित्वके अपने दावेको दोहराते हुअे हम अपना यह पक्का निश्चय प्रगट करना चाहते हैं कि पूर्ण नागरिकताके अधिकारोंकी प्राप्तिके लिअे हम दूना प्रयत्न करेंगे।"

'आन्दोलन' २६ जूनको शुरू हुआ। जिसकी तैयारीके रूपमें मुख्य मुख्य शहरोंमें सामूहिक प्रदर्शन किये गये। कांग्रेसका यह दावा था कि जिसके लिअे १० हजार स्वयंसेवक प्राप्त कर लिये गये हैं। २० जूनको अेक्शन कमेटीने यह विज्ञापित निकाली :

"२६ जूनको अन्यायपूर्ण कानूनोंके खिलाफ शुरू होनेवाले आन्दोलनमें केवल अैसे ही गैर-यूरोपियन भाग लें, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और दक्षिण अफ्रीकाकी भारतीय कांग्रेसकी अेक्शन कमेटी द्वारा नामजद किये गये हों। अनुशासनमें रहनेकी तालीम पाये हुअे 'सक्रिय स्वयंसेवक' ही यह आन्दोलन हाथमें लेंगे। दूसरे कोअी लोग सार्वजनिक रूपमें कानून तोड़नेमें भाग न लें। सारे गैर-यूरोपियन हमेशाकी तरह अपने-अपने काम पर जायं, क्योंकि आम हड़ताल करनेकी आज्ञा नहीं की गयी है।"

आन्दोलनकी योजना भी घोषित कर दी गयी थी। अुसमें तीन अवस्थायें बतायी गयी थीं :

१. चुने हुअे और तालीम पाये हुअे व्यक्ति कुछ बड़े शहरोंमें आन्दोलन करें।

२. स्वेच्छसे विरोध करनेवाले लोगोंके सुसंगठित दल बड़े शहरोंमें आन्दोलन चलायें।

३. जब नेता कार्यके रूपमें अहिंसक विरोधका अुदाहरण पेश कर चुकें, तब जिस आन्दोलनको शहरों और गांवोंमें सामूहिक आन्दोलनका रूप दिया जाय।

यह आन्दोलन (अब अपनी दूसरी अवस्थामें) पिछले छः महीनोंसे चल रहा है और ८ हजारसे अधिक स्त्री-पुरुष अुसमें शरीक हुअे हैं और कैद किये गये हैं। लन्दनके 'अिकॉनामिस्ट' पत्रके जोहानिसवर्गके रिपोर्टरके अनुसार सत्याग्रहियोंका व्यवहार बिलकुल 'निर्दोष' रहा है। मजिस्ट्रेटों और पुलिसने भी व्यवस्थित ढंगसे काम किया है। किसी पर ज्यादातियां नहीं की गयीं। सत्याग्रहियों पर "परवाना लेनेके कानून तोड़नेका, परवाने न

दिखा सकनेका, डाकखानों और रेलवे स्टेशनोंमें 'केवल यूरोपियनोंके ही लिअे' लिखे हुअे रास्तोंसे प्रवेश करनेका, कर्फ्यूके नियम भंग करनेका और निषिद्ध हिस्सोंमें प्रवेश करनेका" अभियोग लगाया जाता है। सजायें देनेमें भी संयम रखा जाता है — आम तौर पर २० दिनकी कैदके साथ दो पाँड जुर्माना किया जाता है, हालांकि कुछ लोगोंको तीन माहकी कैदकी सजा भी दी गयी है और कम अुमरके सत्याग्रहियोंको बेतकी सजा दी गयी है।

लन्दनके 'टाइम्स' पत्रने अपने १६ अगस्तके अंकमें छपे 'दक्षिण अफ्रीकामें अनिश्चितताकी हालत' नामक अग्रलेखमें दक्षिण अफ्रीकाकी मौजूदा राजनैतिक गड़बड़ीमें जिस आन्दोलनका महत्त्व आंकते हुअे लिखा है : "अभी तक आन्दोलनकारियों या पुलिसने बहुत कम या बिलकुल हिंसा नहीं की है। हर पक्ष यह समझता मालूम होता है कि जो भी पहले पशुबल या हिंसाका आश्रय लेगा, वह नैतिक लाभ दूसरेके हाथमें दे देगा; अुसे दुनियाका नैतिक समर्थन नहीं मिलेगा। अैसे चिन्ह दिखाओ देते हैं कि शासन पर जिसका तनाव पड़ने लगा है।"

तनाव और सफलताके ये चिन्ह नीचे दिये जाते हैं :

१. अगाथा हेरिसन (अेक अंग्रेज क्वेकर)को डॉ० जेड० के० मेथ्यूज द्वारा कही गयी अेक नदी पर बांधे हुअे दो पुलोंकी घटना, जिनमें से अेक गोरोंके लिअे और दूसरा कालोंके लिअे है। अेक दलने कानूनका भंग किया (वे जो कुछ करनेवाले थे अुसकी पूर्व सूचना देकर) और वे गिरफ्तार कर लिये गये। दूसरोंने अुनकी जगह ली और अन्तमें यह प्रतिबन्ध अुठा दिया गया।"

२. २८ अगस्तको केपटाअुनके अेक मजिस्ट्रेटने "अन्यायपूर्ण कानूनोंका भंग करनेवाले" अेक अफ्रीकीको निर्दोष घोषित किया, जिस पर ३ अगस्तको केपटाअुन स्टेशन पर अेक यूरोपियन विश्राम-गृहमें बैठनेका अभियोग लगाया गया था। मजिस्ट्रेटने कहा कि पहले और दूसरे दर्जेके गैर-यूरोपियन मुसाफिरोंके लिअे वहां विश्राम-गृहका कोअी प्रवन्ध नहीं था। गैर-यूरोपियन विश्रामगृहोंका साज-सामान भी यूरोपियनोंके विश्रामगृहोंसे "बहुत घटिया" था।

३. लेकिन सबसे ज्यादा महत्त्वकी रिपोर्ट ५ नवम्बरके 'टाइम्स' (लन्दन)में छपी थी, जो अुसके प्रिटोरियाके प्रतिनिधिने भेजी थी :

"नेटालमें कर्फ्यूके नियमोंका भंग करनेवाले अफ्रीकी सत्याग्रहियोंसे निबटनेके लिअे पुलिस नया तरीका अस्तियार कर रही है। नीति यह है कि जब तक अैसे प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण बने रहें, तब तक अुनकी अपेक्षा की जाय।

"कानून-भंगके आन्दोलनने दक्षिण अफ्रीकाकी पुलिसका काम काफी बड़ा दिया है और अधिकारी यह मानने लगे हैं कि वे सत्याग्रहियों पर अितना समय नहीं बिगाड़ सकते; जिसके बजाय अुन्हें अपनी शक्ति गुनाहों और हिंसाको रोकनेमें खर्च करनी चाहिये।"

दक्षिण अफ्रीकाके मजिस्ट्रेटों और जजोंकी यह कार्रवाअी दक्षिण अफ्रीकाके मौजूदा अितिहासमें बहुत बड़ा महत्त्व रखती है; और वह सत्याग्रहियोंको दी गयी मामूली सजाओंमें तथा मौजूदा सरकार और अदालतोंके बीच वैधानिक प्रश्नों पर चलनेवाले झगड़ेंमें दिखायी देती है। पिछले अगस्तमें सरकारने सत्याग्रहके नेता डॉ० मोरोका और डॉ० दादू तथा कार्यकारिणीके दूसरे १८ सदस्यों पर अनिश्चित व्याख्यावाले 'सत्रेशन ऑफ कम्प्युनिस्म अेक्ट' (साम्यवादको दबानेवाला अेक्ट)के भातहत मुकदमा चलानेका निर्णय किया था। अुन पर यह आरोप लगाया गया कि रंगभेदके कानूनों और नियमोंकी खुली अवहेलना करके वे लोग अवैधानिक और अव्यवस्थित साधनोंसे देशके औद्योगिक और सामाजिक संगठनको बदल देना चाहते हैं। दिसम्बरमें ट्रान्सवालकी अदालतके जिस मामलेमें

अपना फैसला दिया। न्यायाधीश रम्फने उनमें से हरएकको ९ माहकी कैदकी सजा दी। लेकिन इस शर्त पर वे सजायें दो सालके लिये मुक्तकी कर दी गयीं कि आगे वे इस अक्टके खिलाफ कोई गुनाह नहीं करेंगे। अपने फैसलेमें न्यायाधीशने कहा, "मेरी रायमें ये मुलजिम अक असी योजनाको बढ़ावा देनेके अपराधी हैं, जो अैसे साधनोंसे—जिनमें गैरकानूनी काम या यूनियनके कुछ कानूनों और म्युनिसिपैलिटीके नियमोंका भंग भी शामिल है—अक्टके अर्थमें राजनैतिक, औद्योगिक, सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन करनेका ध्येय रखती है।" जजने कहा कि सारे मुलजिम जिस अपराधके दोषी पाये गये हैं, वह "वैधानिक साम्यवाद" है। जिस अभियोगका आजके आम तौर पर जाने हुअे साम्यवादसे कोशो सम्बन्ध नहीं है। अन्हें अपील करनेकी अिजाजत दी गयी। ('साभुथ अफ्रीका', ६-१२-५२)

२८ नवम्बरको सरकारने अक आज्ञा निकाली, जिसमें अफ्रीकनोंको कानून तोड़नेके लिये भड़काने और दत्तसे ज्यादा अफ्रीकनोंकी सभा करनेको गुनाह माना गया; और जिसकी सजा तीन सालकी कैद या ३०० पौंड तकका जुर्माना वतायी गयी। इसके जवाबमें युरोपियनोंकी ओरसे यह घोषणा की गयी कि कानून-भंगके आन्दोलनमें अब युरोपियन लोग भी पैट्रिक डंकनके नेतृत्वमें भाग लेंगे। इसके लिये सावधानीसे तैयारी की गयी थी और ८ दिसम्बरको ('टाइम्स'की रिपोर्ट) रंगभेदके अन्यायपूर्ण कानूनोंके खिलाफ किये जानेवाले आन्दोलनमें भाग लेनेके लिये जोहानिसबर्गमें ७ युरोपियनोंको गिरफ्तार किया गया। अन्होंने जर्मिस्टन नामकी अफ्रीकन बस्तीमें प्रवेश किया और वहां अफ्रीकनोंकी अक सभा की। अिन युरोपियनोंके साथ, जो कानून-भंग आन्दोलनमें भाग लेनेवाले पहले गोरे थे, १४ अफ्रीकन और १८ भारतीय थे, जिनमें मणिलाल गांधी भी शरीक थे। अिन सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया।

"बस्तीमें प्रवेश करनेके कुछ ही मिनट बाद लगभग १००० गाते हुअे अफ्रीकनोंका झुण्ड इस दलके पीछे हो लिया। इस जुलूसके साथ पुलिसकी वायरलेस गाड़ियां और खुफिया-विभागकी विशेष शाखाके सदस्य थे। मि० डंकनने अंग्रेजी और सेसुटो दोनों भाषाओंमें बोलते हुअे अफ्रीकनोंसे कहा: 'आज दक्षिण अफ्रीकाके हर तरहके लोग आपके बीच आ गये हैं। वे आपके लिये प्रेम और शांतिकी सीगात लेकर आये हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी करना है बिना कोशो बखेड़ा खड़ा किये और प्रेमकी भावनासे करें।'" ('टाइम्स', ९-१२-५२)

आज भी इस नये आन्दोलनकी कीमत आंकना जल्दी कहा जायगा। अक साल पुराने प्रतिकार-आन्दोलनकी कीमत आंकना भी जल्दी ही होगा। लेकिन यह बहुत साफ है कि दक्षिण अफ्रीकाके जीवन और विचारके अनेक वर्गोंको अन्तरात्माकी इस अपील द्वारा नये विचार और नये काम करनेकी प्रेरणा मिली है।

दक्षिण अफ्रीकाके चर्चोंकी कौंसिल अक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलानेका अनुरोध करती है, जिसमें सब जातियोंके प्रतिनिधि अिकट्टे हों। इस सम्मेलनका अुद्देश्य अैसे अपाय खोज निकालना होगा, जिनसे देशके जीवनमें सारे जातीय दलोंका सहकार सिद्ध किया जा सके। जातीय सम्बन्धोंसे सम्बन्धित संस्था (अिन्स्टिट्यूट ऑफ रेशियल रिलेशन्स) की अपील है कि देशकी सरकार और अफ्रीकन नेताओंका अक सम्मेलन बुलाया जाय। धार्मिक और सामाजिक नेताओंके अक 'अुदार दल'ने समान अधिकारोंकी अुदार नीति पर जोर दिया है। डच रिफार्म चर्चने जिस समस्या पर चर्चा करनेके लिये चर्चोंके सारे नेताओंकी अक कॉन्फरेन्स बुलानेकी घोषणा की है।

प्रिटोरियाके 'दि फ्रेंड' नामक पत्रकी रिपोर्टके मुताबिक ब्लोम-फाअुन्टेनके विशपने अभी हालमें अपनी धर्मसभाके सामने प्रवचन करते हुअे दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका विशेष अुल्लेख किया। अन्होंने कहा कि औसाअियोंके लिये यह अक बुनियादी सिद्धान्त है कि वे सार्वजनिक व्यवस्थाको खतरेमें न डालें; हां, अैसे कानूनको तोड़नेकी बात अलग है, जो नैतिक सिद्धान्तोंके खिलाफ हो। औसाअी शासक जिन लोगों पर शासन करते हैं, उन पर अैसे कानून लादना, जो मनुष्यकी स्वाभाविक प्रतिष्ठा और स्वतंत्रताको सीमित और अपमानित करते हैं और जिनका मुख्य असर निर्दोष कैदियोंसे जेलोंको खचाखच भर देना है, शासकोंका अन्याय है और उनकी औसाअियतके खिलाफ है।" चर्चोंकी विश्व-कौंसिलकी केन्द्रीय समितिकी घोषणामें दुनियाकी रायका सबूत भी हमें मिलता है। चिचेस्टरके विशपकी अध्यक्षतामें केन्द्रीय समितिकी लखनऊमें ता० ३१-१२-५२ से ता० ८-१-५३ तक जो बैठक हुअी, अुसमें समितिने इस बात पर जोर दिया कि "किसी भी जगह जाति या नसलके आधार पर प्रचलित सारे राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव औसाअी धर्मशास्त्रोंमें बतायी गयी औश्वरीय अिच्छाके खिलाफ है। असा समझकर कि मौजूदा जातीय भेदभाव दुनियाके विभिन्न हिस्सोंमें संघर्ष और कड़वाहटको बढ़ा रहा है, समिति सारे सदस्य चर्चोंसे अनुरोध करती है कि वे जातियोंमें मेलमिलाप और समझौता करानेकी औसाअी सेवामें लग जायं और जहां कहीं असा भेदभाव हो, असे दूर करनेका यथाशक्ति प्रयत्न करें।"

जिस अहिंसक प्रतिरोधकी पद्धति यह है कि अन्यायके शिकार हुअे लोग अन्यायपूर्ण कानूनोंको तोड़नेकी कानून द्वारा दी हुअी सजाको स्वेच्छासे स्वीकार करके दमन करनेवालोंकी अन्तरात्मासे अपील करते हैं।

सत्याग्रहियोंके सम्बन्ध पुलिसके साथ मैत्रीपूर्ण हैं। जब कभी अहिंसक प्रतिकारकी योजना बनायी जाती है, तब पुलिसको सूचना की जाती है और पुलिसका अुत्तर भी मैत्रीपूर्ण होता है। मजिस्ट्रेट और जज भी 'मैत्रीपूर्ण' रहे हैं; अन्होंने सत्याग्रहियोंको बहुत हलकी सजायें दी हैं और अितनी तादादमें लोगोंको निर्दोष घोषित करके छोड़ दिया है कि ताज्जुब होता है।

मेरा विश्वास है कि अब चूंकि दक्षिण अफ्रीकाके प्रसिद्ध गोरे लोग भी इस आन्दोलनमें शामिल हो गये हैं, आन्दोलन-समिति आगे बढ़नेका पहलेसे कहीं ज्यादा दृढ़ निश्चय करेगी और मलान सरकारको असे तोड़नेमें ज्यादा हिचकिचाहट महसूस होगी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेसके नये सभापति मुखिया अेलबर्ट लुथुलीने दिसम्बर १९५२ में जोहानिसबर्गमें हुअे कांग्रेसके ४० वें अधिवेशनमें कहा कि मेरी नीति पशुबल या हिंसाका कभी आश्रय न लेनेकी, ज्यादा युरोपियनोंको स्वेच्छासे आन्दोलनमें शरीक होनेका निमंत्रण देनेकी और मेरी जातिकी स्वतंत्रताके मार्गमें खड़ी सारी बाधाओंको हटा देनेकी रहेगी।

१५ जनवरी, १९५३
(अंग्रेजीसे)

जॉन पी० फ्लेचर

आगामी काबिल परीक्षा

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धाकी आगामी काबिल परीक्षा १८, १९ जुलाअी, १९५३ को होगी। फीसके साथ आवेदनपत्र वर्धा कार्यालय पहुंचानेकी आखिरी तारीख १८ जून, १९५३ है। विशेष जानकारीके लिये नीचे दिये गये पते पर लिखें।

२७-४-५३

अमृतलाल नाणावटी
मंत्री,

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा

बम्बयी हिन्दी-हिन्दुस्तानी प्रचारक सम्मेलन

[ता० १२-४-५३ के दिन बम्बयीमें काकासाहब कालेलकरकी अध्यक्षतामें हुअे हिन्दी-हिन्दुस्तानी प्रचारक सम्मेलनमें पास किये गये प्रस्ताव।]

प्रस्ताव - १

भारतके संविधानकी धारा ३४३ और ३५१ को खयालमें रखकर बम्बयी सरकारने राज्यके स्कूलोंमें हिन्दीकी पढ़ाई लांजमी तौर पर शुरू करनेकी दृष्टिसे पाठ्यक्रम आदि तैयार करनेके लिये जो हिन्दी-समिति (पोतदार-समिति) नियुक्त की थी, उसकी यह सम्मेलन कद्र करता है और आशा रखता है कि सरकार समितिकी सभी सिफारिशों पर जल्दीसे जल्दी अमल करेगी। इस सम्मेलनकी रायमें यह बहुत जरूरी है कि पोतदार-समितिकी रिपोर्टमें अके हिन्दी सलाहकार समिति कायम करनेके बारेमें जो सिफारिश की गयी है, उस पर सरकार जल्दीसे जल्दी अमल करे, जिससे हिन्दीके बारेमें जितना भी काम सरकारको करना है उसमें बल और सहायता मिले।

प्रस्ताव - २

यह सम्मेलन मानता है कि राष्ट्रभाषा हिन्दीकी पढ़ाई कॉलेजोंमें पदवी परीक्षा तक अनिवार्य बनायी जाय और इसके लिये राज्यकी युनिवर्सिटियोंमें यथाशीघ्र अन्तजाम किया जाय।

प्रस्ताव - ३

हिन्दीकी पढ़ाई अच्छी हो, जिस दृष्टिसे अहिन्दी-भाषी प्रदेशोंमें शिक्षाका माध्यम हिन्दी रखनेका जो विचार पेश किया जाता है, उसका यह सम्मेलन सख्त विरोध करता है। यह सम्मेलन मानता है कि जिससे वही नुकसान होगा, जो अंग्रेजीको माध्यम बनानेसे हुआ है। यह विचार प्रादेशिक भाषाओंकी प्रगतिके लिये बाधक है और अनुकी अुन्नतिमें रोड़ा बनकर रहेगा। सभी कक्षाओंकी पढ़ाई, यहां तक कि अुच्च और संशोधन तकके लिये शिक्षाका माध्यम बनना प्रादेशिक भाषाका स्वाभाविक हक है और दूसरी किसी भाषाको यह स्थान देना प्रादेशिक भाषाके जिस स्वाभाविक अधिकारको दबा देना है।

प्रस्ताव - ४

संविधानकी धारा ३५१ में राष्ट्रभाषा हिन्दीके स्वरूपका जो बयान किया गया है, उसको खयालमें रखकर यह सम्मेलन मानता है कि हिन्दीका विकास, प्रचार और शिक्षण प्रांतीयता और सांप्रदायिकतासे परे होना चाहिये। और यह काम जिस ढंगसे होना चाहिये कि जिससे दूसरी प्रादेशिक भाषा और हिन्दी दोनों अक-दूसरेकी पूरक और पोषक बनें। अगर ऐसा न हुआ तो भारतकी मिलोजुली संस्कृतिके सब तत्त्वोंको व्यक्त करनेका साधन राष्ट्रभाषा हिन्दी नहीं बन सकती। और सब प्रदेशोंके अलग-अलग भाषा बोलने-वाले लोग उसके साथ पूरा अपनापन महसूस नहीं कर सकते। इसलिये जिस सम्मेलनकी रायमें यह जरूरी हो जाता है कि हिन्दीके शिक्षण, विकास और प्रचारका काम अहिन्दी प्रदेशोंमें काम करने-वाली संस्थाओंके द्वारा हो। चूंकि प्रादेशिक हिन्दी और राष्ट्रभाषा हिन्दी दोनों भिन्न हैं, यह साफ है कि अगर हिन्दीके प्रचारमें गलत-फहमी दूर करनी हो तो यह आवश्यक है कि अहिन्दी प्रदेशोंमें हिन्दी प्रचारका काम करनेवाली संस्थाओंका संबंध ऐसी किसी संस्थासे न होना चाहिये, जो प्रादेशिक हिन्दीका प्रचार करती आयी हो और अब भी करती हो।

प्रस्ताव - ५

बम्बयी सरकारने प्राथमिक स्कूलोंके दर्जे ५, ६, ७ से अंग्रेजीको हटाकर दर्जा ८ से शुरू करनेका जो सिद्धान्त जाहिर

किया है, जिसका यह सम्मेलन स्वागत करता है। लेकिन बादमें अंग्रेजीको ७ वें दर्जेमें अच्छिक रूपसे पढ़ानेकी जो छूट दी गयी है, उसको यह सम्मेलन नापसन्द करता है। अब तो जिससे भी आगे जाकर ५ और ६ कक्षाओंमें भी अंग्रेजी शुरू करनेकी और असे० असे० सी० में वैकल्पिक अंग्रेजीको हटानेकी सूचना आयी है। यह सम्मेलन जिस सूचनाको बड़ी चिन्ताभरी नजरसे देखता है, क्योंकि जिससे न केवल हिन्दीकी पढ़ाईको धक्का लगेगा, परंतु प्राथमिक सात कक्षाओंके अभ्यासमें बाधा आयेगी और बुनियादी तालीम जैसी कोयी चीज नहीं रहेगी।

सम्मेलनकी यह मजबूत राय है कि अंग्रेजीका दर्जा स्वभाषा और राष्ट्रभाषा हिन्दीके बाद ही आ सकता है। जिस वजहसे और जिस खयालसे कि अंग्रेजी लाजमी होनेके कारण हमारे देशके कितने ही बच्चे अुच्च शिक्षासे वंचित रहे हैं, यह सम्मेलन सिफारिश करता है कि बम्बयी-सरकार अपनी पहली नीति पर न केवल कायम रहे, बल्कि अंग्रेजीको ८ वें दर्जेमें अच्छिक रूपसे ही शुरू करे।

प्रस्ताव - ६

हिन्दीके लिये लिपिका सवाल अब संविधान सभाके द्वारा हल हो गया है और अब यह मानी हुयी बात है कि हिन्दीकी लिपि देवनागरी होगी। लेकिन सम्मेलनकी राय है कि विधानकी धारा ३५१ के मुताबिक हिन्दीको अगर भारतकी मिली-जुली संस्कृतिके सब तत्त्वोंको व्यक्त करनेका साधन बनाना है और अगर "हिन्दुस्तानीके रूप, शैली और पदावलिको आत्मसात् करना है", तो यह साफ है कि अुर्दू लिपिको न सिर्फ अच्छिक तौर पर अपनाया चाहिये, बल्कि उसे अुत्तेजन भी देना चाहिये। राष्ट्रभाषा हिन्दीका विकास तभी पूरा होगा, जबकि दोनों लिपियां जाननेवाले लोग काफी तादादमें होंगे।

प्रस्ताव - ७

संविधानकी धारा ३५१ को सामने रखते हुअे यह सम्मेलन हिन्दीके विकासके लिये यह जरूरी समझता है कि अहिन्दी-भाषी लेखकोंको हिन्दीमें किताबें लिखनेके लिये सरकारें और राष्ट्रीय संस्थायें अुत्तेजन दें।

राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी

[दूसरा संस्करण]

गांधीजी

अनु० काशिनाथ त्रिवेदी

कीमत १-८-०

डाकखर्च ०-११-०

नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद-९

विषय-सूची

विषय-सूची	पृष्ठ
बेचैन करनेवाली खबर	मगनभायी देसाजी ६५
हमारा अनोखा मिशन-१	विनोबा ६५
भूदान-यज्ञ और शोषण-निवारण	मगनभायी देसाजी ६८
गांधीवाद	गांधीजी ६९
दक्षिण अफ्रीकामें सत्याग्रह	जॉन पी० फ्लेचर ६९
बम्बयी हिन्दी-हिन्दुस्तानी प्रचारक सम्मेलन	७२
टिप्पणीः	
आगामी काबिल परीक्षा	अ० नाणावटी ७१